

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2120
उत्तर देने की तारीख 11.03.2026

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रिक्तियां

2120 सुश्री सुष्मिता देव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में कुलपति, रजिस्ट्रार, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सभी स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या स्वीकृत पदों को शत प्रतिशत भरने के लिए कोई समयबद्ध रूपरेखा या समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि ऐसी कोई समयसीमा नहीं है, तो बड़े पैमाने पर और लंबे समय से रिक्त पदों होने के बाद भी निश्चित भर्ती कार्यक्रम का निरंतर अभाव क्यों है; और

(घ) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि स्पष्ट समय-सीमा के अभाव के कारण कई संस्थानों में प्रशासनिक गतिरोध और शैक्षणिक व्यवधान बना हुआ है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों / संविधियों / अध्यादेशों / विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। स्वायत्त

संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थाओं के भीतर ही, उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित शासी बोर्ड / कार्यकारी समिति / प्रबंधन बोर्ड में निहित हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका शामिल नहीं है।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और मौजूदा संस्थाओं में विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या और क्षमता विस्तार से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचईआई से मिशन मोड में अपनी संस्थाओं में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने का पुनः अनुरोध किया गया था। सितंबर 2022 से, केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.01.2026 तक (अर्थात् अंतिम रोजगार मेले की तारीख), मिशन मोड में सभी सीएचईआई द्वारा 17878 संकाय पदों सहित कुल 30720 पद भरे गए हैं। इन 30720 पदों में से, उक्त अवधि के दौरान, सीयू, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम ने सामूहिक रूप से 16931 संकाय पदों सहित 28666 पद भरे हैं।

केन्द्रीय वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण संकाय को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व विद्यार्थियों / वैज्ञानिकों / संकाय आदि को आमंत्रित करना शामिल है। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं एक बहु-चरणीय और सुदृढ़ स्क्रीनिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके सीईएचईआई द्वारा की जाती हैं। विभिन्न संस्थाओं के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों का प्रावधान और

विजिटर नॉमिनी आदि को निर्दिष्ट किया गया है ताकि भर्ती में पारदर्शिता और शैक्षणिक दृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया है, जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करता है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाती है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का प्रावधान, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी कई उपाय किए हैं। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने अपनी वैश्विक नवाचार सूची (जीआईआई) रैंकिंग में वर्ष 2013 में 66वें स्थान से वर्ष 2023 में 40वें स्थान पर लंबी छलांग लगाई है। डब्ल्यूआईपीओ के विश्व बौद्धिक संपदा संकेतकों के अनुसार भारत पेटेंट आवेदनों की संख्या में 8वें स्थान (2012 में) से छठे स्थान (2022 में) पर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'अनुसंधान और विकास आंकड़े एक नजर में 2022-23' के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग (एसएंडई) में प्रदान की गई पीएचडी की संख्या के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) 2026 में 54 भारतीय संस्थाओं को स्थान दिया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जो क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2015 में 11 संस्थाओं से बढ़कर क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गया है। आठ भारतीय संस्थाओं को पहली बार रैंकिंग में स्थान मिला है, जो इस संस्करण में जी20 और वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के लिए सर्वाधिक संख्या है, इस प्रकार निरंतर नीतिगत पहलों, सुदृढ़ अनुसंधान और नवाचार क्षमता तथा भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल को रेखांकित किया गया है।
